दलहनों के आयात हेतु सुविधायें

4899. श्रीमती सुषमा स्वराज :

श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार न गत वर्षों के दौरान देश में दलहनों की मांग के अनुसार स्वदेशी संसाधनों से उनकी अनुपलब्धता के कारण दलहनों के आयात की सुविधा प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और ये कब प्रदान की गई तथा क्या सुविधाओं के कारण देश में दालों के उत्पादन में वृद्धि होने की संभावनायें बढ़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) सरकार द्वारा वर्ष 1994–95 के दौरान देश में दलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं और क्या नीति अपनाई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) दहलनों की घरेलू उपलब्धता में आई कमी को पूरा करने के लिये 1983–84 से सामान्य खुले लाइसेंस के तहत 10% आयात प्रभार पर दलहनों के आयात की अनुमति दी गई है । दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम नामक योजना लागू की गई है, । जिसमें बीजों के उत्पादन तथा बीजों, बीज मिनिकिटों, उन्नत कृषि उपकरणों, छिड़काव यंत्रों आदि के वितरण के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है । यह आशा की जाती है कि संयुक्त प्रयासों से दलहनों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा । दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिये दोहरी नीति अपनाई गई है अर्थात बहुफसल तथा एकांतर फसल के माध्यम से क्षेत्र विस्तार तथा मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक आदानों के न्यायोचित उपयोग के माध्यम से निर्यात को बढ़ाना ।

4900. SHRI PRAGAOA KOTATAH:

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to stale:

(a) wliether Government are aware that the farmers are unable to absorb the risks of instability in production levels due to failure of crops, specially in rain-fed areas; and

(b) the action being taken to ease this situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and (b) Yes, Sir.

In order to reduce the risk of crop failure and stablize production in rain-fed areas, the following schemes are being implemented:—

1. National Watershed Development Project for Rainfed Areas.

(2) International/Bilateral projects on Watershed Development with assistance from World Bank, European Commission and Governments of Denmark, Germany & Switzerland.

3. Drought Prone Areas Programme.

4. Desert Development Areas Programe.

5. Integrated Watershed Management in the Catchments of Flood Prone Rivers, (FPR).

6. Soil Conservation in the Catchment of River Valley Project.

7. National Pulses Development Project.

8. Oilseeds Production Programme.

In addition, the fallowing schemes are also being implemented for raising the production and productivity of crops: